EDII

Palash News

September 22, 2023
Page No.03

दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई), अहमदाबाद ने कॉर्पोरेट्स के साथ किया बैठक का आयोजन

3000 दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) को आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराते हुए उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में किया गहन विचार-विमर्श

नई दिल्ली/अहमदाबाद, 21 सितंबर, 2023- भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई), अहमदाबाद ने भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) के सहयोग से कॉर्पोरेट्स के लिए एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। यह बैठक कॉर्पोरेट्स की 'सीएसआर' गतिविधियों के तहत दिव्यांग जनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए 'सुनिश्चित आजीविका को सपोर्ट, एक्टिवेट और निर्मित' करने के मकसद से आयोजित की गई।

अपनी तरह के इस अनूठे कार्यक्रम में दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल, आईएएस, ईडीआईआई के महानिदेशक डॉ. सुनील शुक्ला और ईडीआईआई में परियोजना विभाग (कॉर्पोरेट) के निदेशक डॉ. रमन गुजराल ने भी भाग लिया। उनके साथ डीईपीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारी और प्रमुख कॉर्पोरेट संस्थाओं के सीएसआर अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान दिव्यांगजनों को लेकर बड़े पैमाने पर समाज को संवेदनशील बनाने और उनकी बेहतरी के प्रभावी उपाय शुरू करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही, दिव्यांगजनों के लिए 3,000 नए उद्यमों की स्थापना सुनिश्चित करने की दिशा में भी किए जाने वाले उपायों पर भी विमर्श किया गया। इनमें से 1,500 टैक्नोलॉजी-संचालित और 1,500 सामान्य उद्यम हैं।

इस निर्णायक गोलमेज बैठक में सरकार, कॉर्पोरेट्स और संस्थानों के बीच प्रभावी तालमेल के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने पर विचार-मंथन किया गया। चर्चाएँ स्थायी उद्यम निर्माण के माध्यम से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के विशिष्ट उद्देश्यों के इर्द-गिर्द घूमती रहीं। साथ ही, समाज में उनके पूर्ण समावेश को बढ़ावा देने के लिए उनके लिए बुनियादी ढांचे, दिव्यांग जनों के बारे में धारणा, पर्यावरण, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं के संदर्भ में बेहतर प्रथाओं को अपनाने पर भी चर्चा की गई। उनके लिए कामकाज का एक बेहतर और अनुकूल माहौल तैयार करने और ऐसे व्यावसायिक अवसरों की एक सूची तैयार करने पर भी विचार किया गया, जिसकी सहायता से दिव्यांगजन अपना उद्यम स्थापित करने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। इस बात पर भी मंथन किया गया कि सस्टेनेबल ग्रोथ के लक्ष्यों के साथ दिव्यांगजनों के कल्याण को कैसे जोड़ा जाए और समाज में उस पेशेवर अलगाव को कैसे तोड़ा जाए जो दिव्यांगों को कम वेतन वाली नौकरियों में धकेल देता है।

गंभीर चर्चाओं और निष्कर्षों के आधार पर, भाग लेने वाले कॉर्पोरेट्स ने सहयोग के कुछ प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की। दिव्यांगों के लिए 3000 उद्यम बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहचानी गई कुछ गतिविधियों में शामिल हैं- दिव्यांगों के सामुदायिक एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान; दिव्यांग किशोरों के लिए गहन जीवन कौशल; दिव्यांगजनों के लिए व्यावसायिक अवसरों की सोर्सिंग; दिव्यांगजनों के लिए संवेदीकरण कार्यशालाएँ और क्रेडिट लिंकेज सपोर्ट। साथ ही, सहयोग के इन क्षेत्रों में बेरोजगार दिव्यांगों को अपना व्यवसाय स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए उद्यमी विकास-सह-परामर्श कार्यक्रम (ईजीसीपी) का आयोजन और दिव्यांग-आधारित उद्यमों को सपोर्ट करने के लिए और सूक्ष्म कौशल उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) को भी शामिल किया गया।

दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने अपने भाषण की शुरुआत इस संदेश के साथ की कि भारत चंद्रमा पर पहुंच गया है लेकिन आज भी दिव्यांग लोगों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत में, हमारा दृष्टिकोण समावेशी है लेकिन बुनियादी ढाँचा अभी भी समावेशी नहीं है। उन्होंने सीएसआर के माध्यम से सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने, अपस्किलिंग, दिव्यांगों को ऋण और सलाह प्रदान करने, 'कूलेबिलिटी फैक्टर' के बाद नौकरियों की मैपिंग, उचित आवास प्रदान करने, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के लिए छुट्टियां प्रदान करने सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से दिव्यांगजनों को सपोर्ट करने के मुद्दे उठाते हुए बातचीत की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने कंपनियों के वितरण नेटवर्क में संदेश फैलाने और दिव्यांगजनों को काम पर रखने पर जोर दिया और दिव्यांगजनों के प्रति बड़े पैमाने पर समाज के दृष्टिकोण में बदलाव पर भी बल दिया।